राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 2402/2003

प्रबंध समिति, महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा अपने सचिव के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान न्यायाधिकरण, जयपुर।

2. राज कुमार कांकरिया, गांव सवाईपुर, तहसील कोटरी, जिला भीलवाड़ा के निवासी।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-I, शिक्षा विभाग, भीलवाड़ा।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री रोनिन भंसाली

प्रतिवादी (गण) के लिए : श्री भारत भूषण भोजक

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश</u> (मौखिक)

<u>03/01/2024</u>

1. यहाँ याचिका राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान न्यायाधिकरण, जयपुर द्वारा पारित एक आदेश दिनांक 04.12.2002 (अनुलग्नक 3) के

खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के एक पूर्व कर्मचारी, प्रतिवादी संख्या 2 (राज कुमार कांकरिया) के एक आवेदन को, जो नौकरी छोड़ने के छह साल बाद दायर किया गया था, याचिकाकर्ता को कुछ वित्तीय लाभ देने का निर्देश देने की अनुमति दी गई थी, जो डेढ़ साल की छोटी अवधि से संबंधित है जब वह सेवा में था।

2. वास्तव में, विवाद और संक्षिप्त तथ्यों को अधिक उचित रूप से गोविंद माथुर, जे. (जैसा कि वे उस समय इस अदालत में थे) की अध्यक्षता में मामले को पहले सुनने वाली एक समन्वय पीठ द्वारा पारित एक आदेश के माध्यम से संक्षेपित किया गया है और उपयुक्त होने के कारण, इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "रिट के लिए इस याचिका द्वारा, दिनांक 04.12.2002 के आदेश को चुनौती दी जाती है, जिसके तहत राजस्थान गैर-सरकारी संस्थान न्यायाधिकरण, जयपुर ने राजस्थान गैर-सरकारी संस्थान अधिनियम, 1989 की खंड 21 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिए गए आवेदन को स्वीकार करते हुए उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से उन्हें संशोधित वेतनमान और बोनस देने का आदेश दिया। प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता संस्थान में शिक्षक ग्रेड III के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद उन्होंने 10.02.1990 पर अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान सरकार ने वेतनमान को संशोधित किया और अपने कर्मचारियों को अपने दिनांक 03.03.90 के आदेश के तहत बोनस देने का भी निर्णय लिया जो 01.09.88 से प्रभावी था। प्रतिवादी संख्या 2 ने 1989 के अधिनियम की खंड 21 के तहत आवेदन द्वारा वेतनमान में संशोधन और आदेश दिनांकित 03.03.90 जो 01.09.88 से प्रभावी है, के अनुसार बोनस देने का दावा किया।
>
> उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि न्यायाधिकरण ने 6 साल से अधिक की अत्यधिक

देरी के बाद आवेदन की स्थिरता से संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार किए बिना, याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार कर लिया। यह आगे कहा गया है कि न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 2 पर 1989 के अधिनियम की प्रयोज्यता के तथ्य को निर्धारित किए बिना आक्षेपित आदेश पारित कर दिया।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

स्वीकार करें। नए सिरे से नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व उनके वकील द्वारा किया जा रहा है।

स्थगन आवेदन पर भी पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

तथ्यों और इसमें शामिल कानूनी स्थिति से, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथमदृष्टया एक मजबूत मामला है। इसमें शामिल मुद्दा प्रतिवादी को मौद्रिक लाभ प्रदान करने से संबंधित है और इसलिए, यदि याचिका खारिज हो जाती है, तो याचिकाकर्ता को खारिज करने के बाद भी उसे दिया जा सकता है। दूसरी ओर, संस्थान के लिए राशि की वसूली करना मुश्किल होगा, यदि यह न्यायालय आक्षेपित आदेश के संचालन और प्रभाव पर रोक नहीं लगाता है।

तदनुसार, अंतरिम राहत के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है और राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान न्यायाधिकरण, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 04.12.2002 (अनुलग्नक 3) के आदेश के संचालन और प्रभाव पर रोक लगाई जाती है।"

3. उपरोक्त आदेश पारित होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रति-शपथ पत्र दायर किया गया था, जिसमें न केवल अदालत की टिप्पणियों को पूरी तरह से

संक्षिप्त कर दिया गया है, बल्कि अन्यथा भी, स्वीकार्यता के योग्य या अन्यथा प्रशंसनीय कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

4. आज भी, जो प्रश्न प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अनुत्तरित हैं, ये हैंः-

ए). वह प्रासंगिक समय पर कोई दावा किए बिना अपनी इच्छा से अपनी सेवा को पूर्ण रूप से छोड़ने/इस्तीफा देने के बाद बोनस और संशोधित वेतनमान का लाभ कैसे मांग सकता था?

बी). छह साल की अत्यधिक देरी के बाद विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष उनका आवेदन कैसे बनाए रखा जा सकता था?

5. मामले के गुण-दोष गहराई से विचार किए बिना, तत्काल रिट याचिका के निर्णय के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है कि न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान या काउंटर में दो प्रश्नों के लिए किसी भी प्रशंसनीय स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, या तो इस न्यायालय के समक्ष या जवाबी हलफनामे में या यहां तक कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष, इस न्यायालय द्वारा अपने अंतरिम आदेश में की गई टिप्पणियों को निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया गया है।

6. एक परिणाम के रूप में, मेरा विचार है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन, न केवल सीमा द्वारा वर्जित था, बल्कि अन्यथा भी, बिना किसी योग्यता के था। नतीजतन, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए दिनांकित 04.12.2002 के आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और उसी के अनुसार इसे अलग कर दिया जाता है।

7. तत्काल रिट याचिका को अनुसरण करने वाले परिणाम के साथ अनुमति दी जाती है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।